संख्या- 7 /2026/493 /छिहत्तर-1-2026(2027542)

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) स्थापित किया जाना।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०11031/14/2025-WQ-DDWS दिनांक 12 जनवरी, 2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

2- प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु **'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति, 2024'** प्रख्यापित है, जिसमें ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से वैण्डर के माध्यम से कराए जाने का प्राविधान किया गया है।

3- जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्स के अनुरुप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/ निर्माणाधीन योजनाओं का 10 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यदायी फर्मों द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नियन्त्रणाधीन किया जाना है। योजनाओं को संचालित एवं अनुरक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में पर्याप्त तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध है, जो वर्तमान में जिला तकनीकी इकाई के रूप में कार्यरत है।

4- अतएव भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2026 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर 'जिला तकनीकी इकाई' (DTU) का निम्नवत् गठन कर लिया जाए:-

क्र0 सं0	पदनाम	पद
1.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सिविल	अध्यक्ष/ संयोजन
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि0/यां0	सदस्य

4.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5.	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7.	सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी)	सदस्य
8.	जनपद स्तरीय लैब के कैमिस्ट	सदस्य
9.	भूगर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी सदस्य	सदस्य

5- **जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एवं दायित्व**

(1) सभी प्रकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, राज्य योजनाएं, **National Rural Drinking Water Programme** (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) तथा अन्य ग्रामीण योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाना।

(2) जिला तकनीकी इकाई द्वारा रिऐक्टिव मैन्टेनैन्स को कम करने, नियोजित पूर्वानुमान आधारित एवं मितव्ययी संचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से-

(I) सुजलाम भारत ऐसेट रजिस्ट्री के आधार पर योजनाओं के विभिन्न कम्पोनैन्ट्स हेतु डिजिटल प्रीवैन्टिव मैन्टेनेन्स शिड्यूल तैयार कराना।

(II) विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के जीवनकाल एवं सिस्टम के परफॉरमैन्स के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऐसेट रीप्लेसमैन्ट रणनीति तैयार करना।

(III) विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के फेल्योर, प्लान्ट रीप्लेसमैन्ट तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इन्टैलिजैन्स (ए०आई०) आधारित पूर्वानुमान के आधार पर ऑप्टिमम् भण्डार का प्रबन्धन कराना।

(IV) डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त तकनीकी एवं ऑपरेशनल समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना।

(V) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, स्थान विशेष/ क्षमता के दृष्टिगत सीधे ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा अथवा तकनीकी एजेन्सी/ फर्म को ऐन्गेज करते हुए किया जा सकता है।

(VI) योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्ध तैयार करना, स्कोप ऑफ वर्क परिभाषित करना, सर्विस लैवल, स्टॉफ की आवश्यकता, स्पेयर्स एवं भण्डार की आवश्यकता व सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जिला एवं ग्राम पंचायतों को सुझाव देना।

(VII) पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण, प्रीवैन्टिव मैन्टेनैन्स एवं आपातकाल में रिस्पॉन्स के सम्बन्ध में स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कराना।

(VIII) जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्लानिंग, कमिशनिंग तथा हैण्डओवर (जलार्पण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित कराना।

(IX) योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं नियमित व पर्याप्त मात्रा में गुणवतायुक्त पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लानिंग एवं वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध में सुझाव देना।

6- जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

7- जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा ऑकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते हुए, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को उसके निवारण हेतु सुझाव दिए जाएंगे।

8- जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

9- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(एम.पी. गोयल) 28/2/2026

मुख्य सचिव

संख्या- 7 /2026/493 (1)/छिहत्तर-1-2026 (2027542), तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(7) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10)मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
(11)समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(12)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 28-02-2026 18:12:21

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

No. WQ-11031/14/2025 WQ-DDWS 68

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
National Jal Jeevan Mission

12th Floor, Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003
Dated 12th January, 2026

To
Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary,
Rural Water Supply/ PHE Department,
All States/UTs.

Subject: District Technical Unit (DTU) framework under Jal Jeevan Mission - Regarding.

Madam/ Sir,

This has reference to this Department's letter of even number dated 20.12.2025 wherein States/ UTs were requested to provide views/ comments on the draft District Technical Unit (DTU) framework. It is observed that no comment has been received so far from any State/ UTs. In view of this, the draft framework has now been reviewed and firmed up by technical cell of the Department.

2. In this regard, I am directed to forward herewith the District Technical Unit (DTU) framework for kind information and implementation of the same at the district level. The enclosed framework outlines its objective, scope of work, institutional flow, monitoring mechanisms, water quality surveillance, sustainability and resilience provisions, and human resource arrangements for the DTU. The District Technical Unit is envisaged as a technical bridge between the State agencies, District Water and Sanitation Mission and Gram Panchayats to support implementation and long-term sustainability of rural water supply services.

3. All States/UTs are requested to utilise the DTU framework for strengthening the DWSM support and institutional architecture for facilitating the GPs/VWSCs, in a more focused manner than what is being done by the engineering departments of the States/UTs at present.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

Nitesh Kumar.

(Nitesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Email: nitesh.kumar84@gov.in, wq-ddws@gov.in
Tele No.: 011-2436 4869

Copy to: Engineer-in-Chief/ Chief Engineer, Chief Chemist, In-charge Rural Water Supply, All States/ UTs

District Technical Unit (DTU) Framework

1. Background and Rationale

The Jal Jeevan Mission (JJM) was launched with a transformative goal: to provide every rural household with a functional tap connection. The initial phase focused on rapid infrastructure creation, significantly expanding access to household water supply. As the Mission matured, it became evident that the next challenge lies in ensuring **long-term functionality, sustainability, and reliable service delivery** of the created systems.

Accordingly, JJM's extended phase necessitates a shift from a **construction-led, department-driven model** to a **utility-based, service-oriented governance framework**, wherein rural water supply systems are professionally managed with clearly defined operational roles, performance standards, and accountability mechanisms.

This transition aims to build **technical professionalism** by establishing a **district-level functional unit** for rural water supply management, thereby transforming district officials into professionals capable of ensuring regular and **reliable service delivery** to all households.

2. District Technical Unit (DTU)

To institutionalize the new governance framework, the technical officials and field functionaries of Public Health Engineering Department (PHED) will act as the extended technical arm for rural water operations in the form of **District Technical Unit (DTU)**—the technical backbone of the District Water and Sanitation Mission (DWSM).

Composition of DTU

The DTU will include:

- **All PHED officials** at the district level
- **All water quality officials**
- **Technical Consultants**, if any

The DTU will conduct regular meetings with representative from **Rural Development & Panchayati Raj (Engineering)**, representative from **State Water Board** and technical guidance from **CGWB, SWIC**, and other specialized institutions to ensure technical convergence, informed decision-making, and issue resolution.

District administrations may also **outsource manpower through their own funds** to strengthen DTU capacity wherever required.

3. Adoption of the Dual-Utility System

- GIS-linked **digital asset registries** capturing scheme details from source to tap
- **District Digital Dashboard (JJM)**
- **GP Digital Dashboard (JJM)**

The DTU will ensure that **all water supply schemes**—including **JJM schemes, State schemes, NRDWP schemes, and any other existing rural water supply schemes**—are brought under the **Sujalam Bharat Database**, creating a single unified digital registry for the district.

DTUs will also promote the creation and use of **Digital Twins** for schemes to enable predictive diagnostics, lifecycle planning, and improved operational efficiency.

6. Digital Preventive Maintenance, Asset Strategy & Predictive Analytics

DTU responsibilities include:

- Digitally generating **preventive maintenance schedules** for village-level utilities using Sujalam Bharat asset registries to optimize O&M costs and reduce breakdowns.
- Preparing **mid-term and long-term asset replacement strategies** based on lifecycle analysis and system performance.
- Maintaining **optimal inventory levels** through AI-based predictive analytics for forecasting failures, planning replacements, and efficient resource utilization.

These measures will replace reactive maintenance with **planned, predictive, and cost-effective O&M practices.**

7. Digital Ticketing System for Technical Support

Technical support from DTU to village utilities will be delivered through an integrated **digital ticketing system**, enabling:

- Digital submission of technical and operational issues by GPs/VWSCs
- Automatic mapping of each request to the relevant **Sujalam Bharat ID**
- Digital tracking of response time, troubleshooting actions, and closure
- Real-time monitoring of DTU efficiency through defined digital KPIs

This ensures transparency, accountability, and timely technical resolution.

8. Water Quality Surveillance (WQS) – DTU Responsibilities

Ensuring safe drinking water is a core mandate of the DTU. Its responsibilities include:

The DTU will be responsible for planning, structuring, and managing Operation & Maintenance (O&M) arrangements for rural water supply schemes. O&M may be undertaken directly by Gram Panchayats/VWSCs or through technical agencies engaged for O&M, depending on the local context and capacity. The DTU will guide districts and GPs on preparing O&M contracts, including defining scope of work, service levels, staffing norms, spares and inventory requirements, and safety provisions. All O&M arrangements will be service-level based and performance-linked, with clear indicators such as supply hours, LPCD, pressure, downtime, and water quality compliance.

13. Standardisation of O&M Practices

The DTU will identify common and recurring O&M issues and issue standard operating procedures (SOPs) for troubleshooting, preventive maintenance, and emergency response. It will also prepare a District-specific O&M Manual tailored to local technical and financial conditions.

14. Other Roles of DTU in Implementation and Operations

The DTU will:

- Support JJM implementation, including scheme planning, commissioning, and handover.
- Establish and operate District Command & Control Centres for monitoring scheme performance.
- Integrate and monitor SCADA feeds and other automation systems.
- Undertake futuristic planning, including adoption of alternate technologies to ensure universal household water access.
- Ensure long-term sustenance of water supply systems with regular and reliable service delivery.

15. Conclusion

The DTU framework represents a critical institutional reform under JJM, enabling the transition to a **utility-based, digitally governed rural water supply system**. The DTU will strengthen PHED through digital tools, professional capacity, outsourcing, and inter-departmental collaboration, the Mission creates a resilient structure focused on **functionality, transparency, accountability, and sustainability.**

Through this framework, rural water supply systems will be professionally managed, citizen-centric, and capable of delivering reliable services in alignment with India's vision of **Viksit Bharat 2047**.